सब्सिडी की निगरानी के लिए बनेगा नया डैशबोर्ड

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने एकीकृत पोर्टल के लिए प्रक्रिया शुरू की

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में सब्सिडी की ट्रैकिंग करने के लिए नया डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। यहां सभी सब्सिडी का एकीकृत पोर्टल होगा। ये शुरुआत आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने की है।

निवेशकों की सुविधा के लिए बन रहा डैशबोर्ड पूरी तरह आटोमेशन पर आधारित होगा। इसके बाद सब्सिडी कोई रोक नहीं सकेगा। ये फैसला इसलिए किया गया, क्योंकि कई केस ऐसे सामने आए, जिनमें फाइल सालों से अधिकारियों की मेजों पर ही धूल खा रही थी। सब्सिडी को लेकर विभागों की शिकायतें सबसे ज्यादा रहती हैं। निवेशकों के कई मामले भी

कई मामलों में सब्सिडी छह साल तक अटकी, अफसरों की मेजों पर धूल खा रहीं फाइलें

प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी से जुड़े हैं। इसके मद्देनजर आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में एक डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। जहां सारी सब्सिडी का एकीकृत पोर्टल होगा। इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। ये प्रक्रिया लागू होने के बाद किसी स्तर पर सब्सिडी रोकी नहीं जा सकेगी।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि अभी कई केस सामने आए, जो एम्पावर्ड कमेटी तक पहुंचे ही नहीं थे। अधिकारियों की टेबल पर ही पत्रावलियां अटकी थीं। इनमें कई मामले छह-सात साल पुराने थे। इनका जल्द निस्तारण करने के साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी निवेशक की सब्सिडी न रोकी जाए। कोई दिक्कत हो तो उसे दूर करें। पर निवेशक के साथ जो वादा किया है, उसे जरूर पूरा करें।

उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में सब्सिडी की मद में 400 करोड़ रुपये का बजट था, जिसकी तुलना में 408 करोड़ रुपये दी गई। इस वित्त वर्ष ये बजट लगभग 500 करोड़ रुपये का है। सब्सिडी से जुड़े मामलों के लिए एक टीम सर्वे करेगी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर तत्काल सब्सिडी मिल जाएगी।